

न्यूज़ डुडे

स्वास्थ्य मंत्री ने देश में टीबी के विरुद्ध संघर्ष में प्रगति की समीक्षा की

- स्वास्थ्य मंत्री ने क्षय रोग (टीबी) के विरुद्ध जन आंदोलन की समीक्षा करने के लिए सभी राज्यों के साथ आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। यह अभियान समर्थन, संचार और सामाजिक एकजुटता (Advocacy, Communication and Social Mobilization: ACSM) पर आधारित है।
- टीबी कार्यक्रम के साथ कार्य करने वाले सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन करने के लक्ष्य का समर्थन करने की योजना निर्मित की है। ज्ञातव्य है कि यह सतत विकास लक्ष्यों के तहत वर्ष 2030 के लक्ष्य से पांच वर्ष पूर्व की प्रतिबद्धता है।
- टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जो प्रायः फेफड़ों को सर्वाधिक प्रभावित करता है।
- यह एक संक्रामक रोग है, जो वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होता है। यह शरीर के अन्य अंगों जैसे किडनी, मेरुदंड और मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है।
- वर्ष 2019 में, टीबी के कुल नए मामलों में से 87% मामले उन 30 देशों से थे, जो टीबी से सर्वाधिक रूप से प्रभावित हैं। टीबी के कुल नए मामलों में से दो-तिहाई मामलों के लिए भारत सहित आठ देश उत्तरदायी हैं।
- यह रोग साध्य तथा निवारण योग्य है। आइसोनियाज़िड, रिफैम्पिन, एथेम्ब्यूटोल और पायरज़ीनामाईड टीबी के उपचार के लिए स्वीकृत 4 रोगानुरोधी दवाएं हैं।
- भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई पहलें:
- संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Revised National Tuberculosis Control Programme: RNTCP) का नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (National Tuberculosis Elimination Programme: NTEP) कर दिया गया है।
- ई-निक्षय प्लेटफॉर्म: यह टीबी नियंत्रण के लिए वेब-सक्षम रोगी प्रबंधन प्रणाली है।
- टीबी रोगियों को उनके उपचार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निक्षय पोषण योजना आरंभ की गई है।
- टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान संचालित किया जा रहा है।



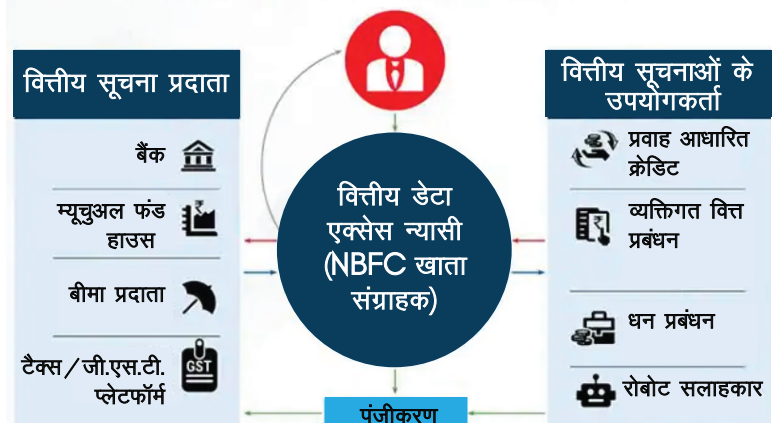
ऋण प्रदायगी व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु खाता संग्राहक (Account Aggregator) प्रणाली आरंभ की गई है

- भारत ने एक डेटा साझाकरण प्रणाली के रूप में खाता संग्राहक प्रणाली का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य निवेश तथा ऋण के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है।
- खाता संग्राहक एक वित्तीय इकाई है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति के सभी वित्तीय डेटा को प्राप्त करके समेकित किया जा सकता है। यह इस डेटा को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है, जिससे पाठक किसी व्यक्ति की विभिन्न वित्तीय धारिताओं को सरलता से समझकर विश्लेषण कर सके।
- वर्ष 2016 में, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने "नैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- खाता संग्राहक (अकाउंट एग्रीगेटर) (रिज़र्व बैंक) निर्देश [Non-Banking Financial Company & Account Aggregator (Reserve Bank) Directions], 2016" जारी किए थे।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-1 के तहत नैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के एक विशेष वर्ग के रूप में खाता संग्राहक को,
- वित्तीय डेटा का सुलभ साझाकरण सुनिश्चित करना तथा
- उपयोगकर्ताओं के लिए पूर्व विकसित सहमति ढांचा प्रदान करना होता है।
- महत्व: फर्म को समय पर मात्रात्मक तथा गुणात्मक डेटा की उपलब्धता होगी। इससे, उन्हें लघु व्यवसायों की उधार पात्रता का आकलन करने, किसी व्यक्ति के लिए धन प्रबंधन उत्पाद की संस्तुति करने या किसी परिवार के लिए बीमा पॉलिसी तैयार करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।
- विश्व के किसी अन्य देश ने ऐसा विस्तृत डेटा-साझाकरण ढांचा विकसित नहीं किया है, जिसे 50 मिलियन से अधिक व्यवसायों तथा एक बिलियन से अधिक लोगों को समाहित करने के लिए परिनियोजित किया जा सकता है।

खाता संग्राहक ढांचा

RBI / भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) / पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) / भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा एक खाता संग्राहक वास्तविक समय में वित्तीय जानकारी साझा करने की सहमति प्रदान करेगा

डेटा हेतु अनुरोध साझा करने हेतु सहमति एन्क्रिप्टेड डेटा प्रवाह

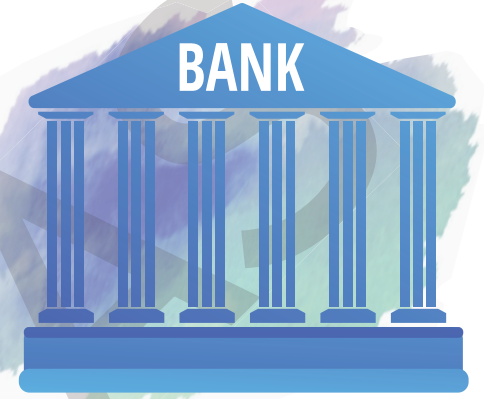


Source: Sahamati

f t i n moneycontrol

वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से ऋण प्रबंधन कार्य को पृथक करने पर चर्चा की

- RBI से ऋण प्रबंधन को पृथक करने का विचार पूर्व में वित्त विधेयक, 2015 (और RBI द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2000-01 में भी) में सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी (Public Debt Management Agency: PDMA) के रूप में प्रस्तावित किया गया था। ज्ञातव्य है कि इसके लिए RBI अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है।
 - PDMA केंद्र सरकार की आंतरिक और बाह्य देनदारियों का समग्र रूप से प्रबंधन करेगी और एक शुल्क के प्रतिफल में ऐसे मामलों पर परामर्श प्रदान करेगी।
 - एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में, सरकार ने ऋण प्रबंधन के लिए RBI के तहत ही, परन्तु सलाहकारी शक्तियों के साथ एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ (Public Debt Management Cell: PDMC) की स्थापना की है।
- RBI के ऋण प्रबंधन कार्यों को पृथक करने की आवश्यकता:
 - सभी सरकारी उधारियों को एक ही संस्था के अंतर्गत लाना।
 - व्यापक संस्थागत सुधार को प्रोत्साहित करना। इससे बॉण्ड बाजार सुदृढ़ होगा और सार्वजनिक ऋण के संबंध में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, जिससे एक सक्षम प्रणाली का निर्माण होगा।
 - संसाधनों के एक वृहद पूल से निधियों का दोहन करना।
 - वैश्विक स्तर पर स्वीकृत प्रणाली।
- PDMA से संबंधित मुद्दे:
 - एक नई एजेंसी को उत्तरदायित्व के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप बाजार में उतार-चढ़ाव की आशंका।
 - बैंकों के स्वामी के रूप में सरकार और ऋण जारीकर्ताओं के मध्य हितों का टकराव।
 - RBI के सापेक्ष PDMA की क्षमता पर संशय।



न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) ने अपने वैश्विक पहुंच के दायरे को विस्तृत करते हुए नवीन सदस्यों को स्वीकृति देना आरंभ किया

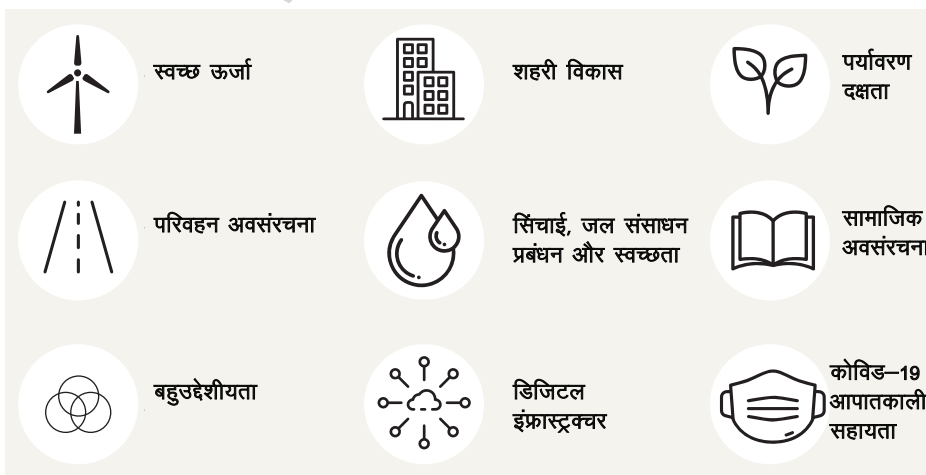
- न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE), उरुग्वे और बांग्लादेश को अपने प्रथम नए सदस्य देशों के रूप में स्वीकृति प्रदान की है।
 - NDB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने वर्ष 2020 में अपनी सदस्यता का विस्तार करने के लिए वार्ता आरंभ की थी।
 - NDB की सदस्यता का विस्तार उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रमुख विकास संस्थान के रूप में स्थापित होने की बैंक की रणनीति के अनुरूप है।
- NDB का मुख्यालय शंघाई में स्थित है। इसे फोर्टलेजा में छठे ब्रिक्स/BRICS (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) शिखर सम्मेलन (2014) के दौरान स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों में सतत विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण करना है। (इन्फोग्राफिक देखें)।
 - NDB के पास 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अधिकृत पूंजी है। यह संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा अभिदाय हेतु मुक्त है।
 - वर्ष 2018 में, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ था।
 - ज्ञातव्य है कि भारत वर्ष 2021 के लिए ब्रिक्स समूह का अध्यक्ष है।
- NDB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) से भिन्न है। AIIB की अध्यक्षता चीन द्वारा की जाती है, इसका मुख्यालय बीजिंग में स्थित है। वर्ष 2016 में, भारत 57 देशों के साथ AIIB का संस्थापक सदस्य बना था।
 - AIIB की सदस्यता बढ़कर 103 देशों तक पहुंच गई है।

उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया में फेक न्यूज व सांप्रदायिक झुकाव पर चिंता व्यक्त की है

- उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में तब्लीगी जमात की बैठक के मामले में याचिका की सुनवाई की पृष्ठभूमि में, "फेक न्यूज" और सांप्रदायिक झुकाव से युक्त सूचना का प्रसार करने वाले वेब पोर्टलों और यूट्यूब (YouTube) जैसी संस्थाओं पर जवाबदेही लागू करने के लिए एक विनियामक तंत्र के अभाव पर खेद व्यक्त किया है।
 - इससे पूर्व, उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2018 में तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ वाद में सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भेड़ की हिंसा (Mob Violence) और किसी भी तरह की लिंगिंग को भड़काने वाले संदेशों पर नियंत्रण लगाने का निर्देश दिया था।
- हाल ही में, केंद्र ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 [Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021] का प्रवर्तन किया है। इसका उद्देश्य मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और नागरिकों के सही सूचना प्राप्त करने के अधिकार के मध्य संतुलन स्थापित करना है।

○ नियमों की प्रमुख विशेषताएं

- भारत की संप्रभुता एवं अखंडता से संबंधित अपराध के मामले में "सूचना के प्रथम प्रवर्तक" की पहचान की आवश्यकता होगी।
- त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र को अनिवार्य किया गया है।
- केंद्र सरकार का दावा है कि डिजिटल समाचार प्रकाशकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना डिजिटल समाचार प्रकाशकों की वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करती है, बल्कि केवल जवाबदेही का एक तंत्र प्रदान करती है।



अन्य सुर्खियाँ

 लोकसभा उपाध्यक्ष	○ लोकसभा (LS) में उपाध्यक्ष का पद विगत 830 दिनों से रिक्त है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के उल्लंघन को प्रतिबिंबित करता है। ○ उपाध्यक्ष के बारे में— ➤ संविधान के अनुच्छेद 93 में उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ➤ सामान्यतया आम चुनाव के उपरांत लोकसभा की प्रथम बैठक के दौरान लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक को उपाध्यक्ष के पद हेतु चयनित किया जाता है। ➤ परंपरा के अनुसार भारत में विपक्षी दल को ही इस पद नियुक्त किया जाता रहा है। ➤ वह लोकसभा अध्यक्ष की मृत्यु या रोग के कारण अवकाश या अनुपस्थिति के दौरान पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है।
 पत्रकार कल्याण योजना (JWS)	○ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने JWS के मौजूदा दिशा-निर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। ○ इस योजना के तहत पत्रकारों व उनके परिवारों को तत्काल आधार पर एकमुश्त अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। ➤ साथ ही, पत्रकार की मृत्यु के कारण उत्पन्न आर्थिक विषमता की स्थिति में परिवार को 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। ○ JWS के तहत मृत्यु की स्थिति में तथा अन्य मामलों में अनुग्रह भुगतान की मात्रा में संशोधन की आवश्यकता की जांच का दायित्व समिति को सौंपा गया है। ➤ यह समिति इस योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकारों के बीच भेदभाव या समानता के पहलू का भी परीक्षण करेगी।
 क्रेडिट बैंक और ग्लू ग्रांट योजना	○ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में, 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा क्रेडिट बैंक के साथ-साथ हाल ही में घोषित ग्लू ग्रांट योजना जैसी पहलों के भी उपयोग को आरम्भ किया जाएगा। ○ क्रेडिट बैंक या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक डिजिटल बैंक का ही रूप है। इसमें किसी भी पाठ्यक्रम में छात्र द्वारा अर्जित क्रेडिट (अंकों) को शामिल किया जाता है। इससे छात्रों को सर्वोत्तम पाठ्यक्रम या उनकी आवश्यकताओं अथवा योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम चयन में सहायता मिलेगी। ○ शहरों को शिक्षा हब के रूप में विकसित करने के लिए 9 शहरों में ग्लू ग्रांट योजना को लागू किया जाएगा। इसे एक छत्र संरचना के द्वारा एक ही शहर के विभिन्न संस्थानों के मध्य संसाधनों और उपकरणों (छात्रों के लिए गतिशीलता सहित) के साझाकरण के माध्यम से लागू किया जाएगा।
 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार	○ बांग्लादेशी वैक्सीन वैज्ञानिक (डॉ. फिरदौसी कादरी) व पाकिस्तान के सूक्ष्म-ऋण के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका हेतु प्रसिद्ध (मोहम्मद अमजद साकिब) रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 2021 के पांच प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। ○ वर्ष 1957 में स्थापित, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण के रूप में संदर्भित किया जाता है। ➤ इसका नाम फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति (1953-57) रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है। ➤ रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन (RMAF) प्रत्येक वर्ष एशिया में उन व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित करता है, जिन्होंने विशिष्ट सामाजिक योगदान दिया है।
 ब्ल्यू स्ट्रैग्लर (Blue straggler)	○ भारतीय शोधकर्ताओं ने पहली बार ब्ल्यू स्ट्रैग्लर का व्यापक विश्लेषण किया है। ○ ब्ल्यू स्ट्रैग्लर अन्य सितारों की तुलना में अपेक्षाकृत अत्यधिक विशाल और नीले रंग के होते हैं। ये एक तारे का दूसरे तारे में विलय होने पर निर्मित होते हैं। ➤ ये तारे मुख्य रूप से प्राचीन और विशाल तारों के समूहों में मौजूद होते हैं। ➤ 54% से अधिक ब्लू स्ट्रैग्लर निकट के बाइनरी साथी तारे से वृद्ध पैमाने पर होने वाले द्रव्यमान स्थानांतरण के परिणामस्वरूप निर्मित होते हैं। 30% संभावित रूप से 2 तारों के टकराव के माध्यम से निर्मित होते हैं और 10-16% ब्लू स्ट्रैग्लर दो से अधिक तारों की परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से निर्मित होते हैं।
 जलवायु वित्त नेतृत्व पहल {Climate Finance Leadership Initiative (CFLI)}	○ यह भारत के अल्प कार्बन की ओर संक्रमण में वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करने के क्रम में निजी पूंजी की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आरंभ की गई एक उद्योग नेतृत्व वाली पहल है। ➤ इसे 11वें भारत-यूनाइटेड किंगडम आर्थिक और वित्तीय संवाद के दौरान आरंभ किया गया था। ○ इसका उद्देश्य सार्वजनिक, निजी और बहुपक्षीय पहलों के माध्यम से भारत में पूंजी उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। इससे देश को वर्ष 2015 के पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। इन प्रतिबद्धताओं में वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के 33-35 प्रतिशत तक उत्सर्जन तीव्रता को कम करने का संकल्प शामिल है। ➤ CFLI की अध्यक्षता जलवायु महत्वाकांक्षा और समाधान पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत द्वारा की जाती है।

 औषधीय पादपों की कृषि को बढ़ावा देना	○ इस अभियान को आजादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (NMPB) द्वारा आरंभ किया गया है। ○ आगामी एक वर्ष में देश भर में 75,000 हेक्टेयर भूमि पर औषधीय पादपों की खेती की जाएगी। ➤ पादपों की 5 प्रजातियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है— रात में खिलने वाली चमेली (पारिजात), स्वर्ण सेब (बेल), मार्गोसा ट्री (नीम), इंडियन जिनसैंग (अश्वगंधा) और इंडियन ब्लैकबेरी (जामुन)। ➤ कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और महाराष्ट्र के पुणे से की गई है। ○ इससे किसानों की आय बढ़ाने और हरित भारत के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी।
 ईट राइट स्टेशन	○ हाल ही में, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India: FSSAI) ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 'ईट राइट स्टेशन' प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया है। ➤ चंडीगढ़ यह प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पांचवां रेलवे स्टेशन है। ○ FSSAI के 'ईट राइट इंडिया' अभियान के एक भाग के रूप में ईट राइट स्टेशन पहल का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर स्थिर भोजन प्रबंधन इकाइयों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। ➤ FSSAI ने 'ईट राइट इंडिया' आंदोलन के माध्यम से सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और उचित भोजन सुनिश्चित करने हेतु (देश की खाद्य प्रणाली के रूपांतरण के लिए) वृहद पैमाने पर प्रयास आरम्भ किए हैं।
 सुर्खियों में रहे स्थल	बगराम एयरबेस, अफगानिस्तान ○ इसे प्रथम बार सोवियत संघ द्वारा निर्मित किया गया था। इस एयरबेस की काबुल (अफगानिस्तान) से निकटता के कारण इसे लगभग 20 वर्षों तक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सबसे बड़े एयरबेस के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। ○ संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व दूत निक्की हेली द्वारा जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि चीन बगराम एयरबेस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने हेतु प्रयासरत है। ○ चीन हवाई युद्ध के दौरान भारत के विरुद्ध अपने सामरिक अलाप (भारत-चीन सीमा पर स्थित तिब्बत की अत्यधिक ऊंचाई के कारण एयरबेस एवं युद्धक विमानों के परिचालन में कठिनाई होने के कारण) के निवारण हेतु इस एयरबेस का उपयोग कर सकता है। 



8468022022, 9019066066



www.visionias.in



/c/VisionIASdelhi



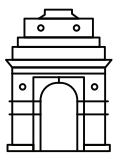
/Vision_IAS



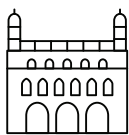
/visionias_upsc



/VisionIAS_UPSC



दिल्ली



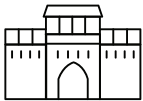
लखनऊ



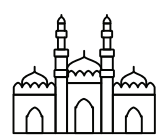
जयपुर



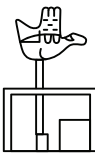
हैदराबाद



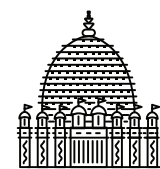
पुणे



अहमदाबाद



चंडीगढ़



गुवाहटी